मेघालय हिंसा के उत्तरदायी कारक

लेखक- अभिषेक साहा (संपादक)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (आंतरिक सुरक्षा) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

06 मार्च, 2020

"सीमा पर झड़प, शिलांग में छुरा घोंपने की घटना और तीन लोगों की मृत्यु ने मेघालय की जातीय जटिलताओं को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। इस आलेख में हम जानेंगे कि कौन-कौन से समुदाय इस संघर्ष में शामिल हैं और सीएए की इसमें क्या भूमिका है?"

पिछले हफ्ते, मेघालय में जातीय हिंसा ने तीन लोगों की जान ले ली। बांग्लादेश की सीमा के पास एक गाँव में एक खासी आदिवासी की हत्या कर दी गई, जिसके बाद शिलांग में और कई अन्य जगहों पर नकाबपोश हमलावरों द्वारा हमले किए गए जिससे दो गैर-आदिवासी पुरुषों (जो मुसलमान थे) की मौत हो गई। नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के पारित होने के बाद से यह तनाव और बढ़ गया है जो मेघालय की जातीय जटिलताओं को भी रेखांकित करता है।

बहु-जातीय मेघालय

मेघालय 1972 में असम से बाहर होने के बाद एक राज्य बना। इससे पहले, मेघालय की राजधानी शिलांग, असम की राजधानी हुआ करती थी। बांग्लादेश के साथ 443 किलोमीटर की सीमा को साझा करते हुए, मेघालय ने दशकों से उन क्षेत्रों से प्रवासन को देखा है जो अब बांग्लादेश में हैं, साथ ही इसने असम के माध्यम से विभिन्न भारतीय राज्यों से भी प्रवासन को देखा है। स्वदेशी समूहों के अलावा, मेघालय के निवासियों में बंगाली, नेपाली, मारवाड़ी, बिहारी और विभिन्न अन्य समुदायों के लोग शामिल हैं।

मेघालय एक आदिवासी बहुसंख्यक राज्य है। सरकारी नौकरियों में स्वदेशी खासी, जयंतिया और गारो को 80% आरक्षण प्राप्त है। 1978 में स्थापित खासी छात्र संघ (केएसयू) जैसे समूहों ने लगातार चिंता व्यक्त की है कि बांग्लादेश से अवैध प्रवासन और अन्य राज्यों से "बाहरी लोगों" के आगमन से स्वदेशी समुदायों को नुकसान हुआ है।

मेघालय हिंसा: सीएए संदर्भ

दिसंबर में संसद द्वारा पारित सीएए, भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने की पात्रता को बांग्लादेश (तीन देशों के छह धार्मिक समूहों के बीच) के हिंदुओं के लिए मानदंडों को सरल बनाता है। इस कानून को मेघालय सहित पूर्वोत्तर में पहले से ही विरोध का सामना करना पड़ा था। आखिरकार, केंद्र ने फैसला किया कि सीएए छठी अनुसूची क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। संविधान की छठी अनुसूची में पूर्वोत्तर के कुछ क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान हैं, जिनमें भी शामिल है।

इस बड़ी छूट के बावजूद, मेघालय में चिंताएँ बनी हुई हैं और इनर लाइन परमिट (ILP) प्रणाली की माँगों ने नई गति प्राप्त की है। यदि ILP प्रणाली की शुरुआत की जाती है, तो किसी भी अन्य राज्य के प्रत्येक भारतीय नागरिक को मेघालय जाने के लिए समयबद्ध अनुमति की आवश्यकता होगी।

तनावों को भड़काने वाले संकेत

पिछले चार दशकों में बंगाल और नेपाल सहित गैर-आदिवासियों पर लक्षित मेघालय में हिंसा की कई घटनाएँ हुई हैं। नवीनतम तनाव इनर लाइन परमिट के कार्यान्वयन पर एक निरंतर अभियान और सीएए पर पूर्वोत्तर में अशांति बढ़ी है, जिसके कारण दो महीने पहले असम में छह मौतें हुई थीं।

पिछले सप्ताह शुक्रवार को, केएसयू की एक टीम इन दोनों मुद्दों पर बैठक करने के लिए बांग्लादेश सीमा के पास इचमाती गाँव में गई थी। इस अभियान के दौरान छात्र कार्यकर्ताओं और गैर-आदिवासी ग्रामीणों के बीच झड़प हुई, जिससे एक खासी व्यक्ति मारा गया।

मेघालय का विलय

- 1947 में गारो और खासी क्षेत्र के शासकों ने भारत के नए स्वतंत्र देश में प्रवेश किया।
- मेघालय, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित एक छोटा पहाड़ी राज्य है, जो 2 अप्रैल 1970 को असम राज्य के भीतर एक स्वायत्त राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, जिसमें संयुक्त खासी और जयंतिया हिल्स और गारो हिल्स जिले शामिल थे।

अन्य तथ्य

- 21 जनवरी, 1972 को, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 के तहत त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय राज्य पूर्ण विकसित राज्य बन गए।
- स्वतंत्रता के समय, उत्तर पूर्व की क्षेत्रीय संरचना में पुराने असम प्रांत, पहाड़ी जिले और पूर्वोत्तर सीमा के नॉर्थ ईस्टर फ्रंटियर ट्रैक्ट्स (NEFT) के असम के क्षेत्र शामिल थे।
- 1949 में, मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों का दर्जा दिया गया था। नागालैंड को 1 दिसंबर 1963 को राज्य का दर्जा दिया गया।
- भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के अनुसार, मेघालय को असम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम 1969 के माध्यम से एक स्वायत्त राज्य बनाया गया था।
- 1986 के मिजो समझौते के अनुसार, मिजोरम 1987 में भारत के पूर्ण राज्य के रूप में उभरा।

इस घटना ने राज्य के अन्य हिस्सों में हिंसा भड़काई और फिर गैर-आदिवासी व्यक्तियों को निशाना बनाया गया। शिलांग में, कम से कम 10 व्यक्तियों को नकाबपोश व्यक्तियों ने चाकू मार दिया, जिससे असम के एक मुस्लिम की मृत्यु हो गई। पीरकेन नामक गाँव में एक और मुस्लिम (जिसने खासी महिला से विवाह किया था) की हत्या कर दी गई।

सीमा पर विवाद

इचमाती में मिश्रित समुदाय रहते हैं, जिनमें न सिर्फ बंगाली और हिंदू बड़े पैमाने पर हैं, बल्कि मणिपुरी और हजोंग भी शामिल हैं। खासी कार्यकर्ता की हत्या के बाद पाँच बंगालियों और तीन मणिपुरियों को गिरफ्तार किया गया है। केएसयू के एक सदस्य ने कहा कि इचमाती में गैर-आदिवासी न तो सीएए का विरोध करते हैं और न ही आईएलपी चाहते हैं, इसलिए प्रतिनिधिमंडल पर हमला किया गया।

'द शिलांग टाइम्स' के संपादक पेट्रीसिया मुखीम ने कहा, "सीएए-आईएलपी मुद्दे ने समस्याओं को और तेज कर दिया है और सामान्य समय में एक-दूसरे के साथ व्यापार करने वाले लोगों के बीच भी विभाजन को तेज किया है।"

मुखीम ने कहा कि इचमाती और पास के भोलागंज में खासी और गारो से ज्यादा बंगाली रहते हैं। "ऐसा तब होता है जब नई सीमाएँ उन देशों के बीच खींची जाती हैं जो कभी एक-दूसरे का हिस्सा रहे थे। वास्तव में पिछले साल ऐसे कई मौके आए जब सीमा पार से आए लोगों ने शीला, इचमाती आदि में कथित रूप से आदिवासियों पर हमला किया।"

शिलांग, तब और अब

शिलांग ने पिछले चार दशकों में कई बार "बाहरी लोगों" के खिलाफ हिंसा देखी है। 1979 में बंगालियों, 1987 में नेपालियों और 1992 में बिहार के लोग निशाने पर थे। 2018 में, शिलांग में खासी और पंजाब मूल के दलित सिखों के बीच झड़पें देखी गईं, जिनके पूर्वज 100 साल पहले वहाँ आकर बसे थे।

2013 में एक निबंध में, इतिहासकार बिनायक दत्ता, जो उत्तर-पूर्वी हिल विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, ने वर्णन किया कि कैसे बंगालियों, असमियों, नेपालियों, मारवाड़ियों और बिहारियों ने मिलकर "शिलांग के बहु-जातीय स्थान" को विकसित किया था। आजादी के बाद सभी का पतन शुरू हुआ। "जनजातियों के हित की रक्षा के लिए स्थापित संवैधानिक संस्थान इन जनजातीय क्षेत्रों को जनजातीय आधिपत्य के अनन्य क्षेत्रों में परिवर्तित करने के अवसरों के रूप में लोकप्रिय माने जाते रहे हैं।"

2003 में, राजनीतिक वैज्ञानिक सी.आर.लिंगदोह और एल एस गासाह ने इकनोमिक एंड पोलिटिकल वीकली में लिखा था कि "मेघालय राज्य में अवैध रूप से रहने वाले 'विदेशियों' का मुद्दा सबसे महत्त्वपूर्ण मुद्दों में से एक था, जो 1970 और 1980 के दशक में राज्य की राजनीति पर हावी था। 1979 में, राज्य को पहली बार बनाए जाने के बाद से इस पर संकट के बादल मंडराने लगे थे। "उन्होंने कहा, "इन सभी घटनाओं में, गैर-आदिवासी समुदाय हमेशा अंत में ही रहता था।"

इनर लाइन परमिट (ILP) क्या है?

- यह एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है जिसे भारत सरकार द्वारा किसी भारतीय नागरिक को संरक्षित क्षेत्र में सीमित समय के लिये आंतरिक यात्रा की मंजूरी देने हेतु जारी किया जाता है।
- इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन रूप से आवेदन करने के बाद प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें यात्रा की तारीख और उन क्षेत्रों को निर्दिष्ट करना होता है जहाँ ILP धारक यात्रा करना चाहते हैं।
- आगंतुकों को इस संरक्षित क्षेत्र में संपत्ति खरीदने का अधिकार नहीं होता है।
- इस दस्तावेज को 'बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन' एक्ट, 1873 के तहत जारी किया जाता है।

पुरानी चिंताएँ, पुनर्जीवित

हाल ही की हिंसा में, 52 वर्षीय, जड्डू चौधरी को दो बार कंधों में छुरा घोंपा गया। वे असम के बंगाली बहुल सिलचर शहर में रहते हैं और 1982 से शिलांग में सब्जियाँ बेच रहे हैं। फिर भी, उन्होंने कहा, यह पहली बार था जब उन्होंने शिलांग में नकाबपोश लोगों को घूमते हुए देखा था।

पृष्ठभूमि

- सरल शब्दों में कहें तो ब्रिटिश सरकार ने इनर लाइन सिस्टम इसलिए लागू किया था क्योंकि नगालैंड और अन्य क्षेत्रों में प्राकृतिक औषधि और जड़ी-बूटियों का प्रचुर भंडार था जिसे ब्रिटिश सरकार इंग्लैंड भेजा करती थी। इन पर किसी और की नजरें नहीं पड़ें इसके लिए सबसे पहले नागालैंड में इसकी शुरूआत की थी।
- आजादी के बाद भी ऐसी व्यवस्था लागू है। अब इसके पीछे तर्क दिया जाता है कि इन राज्यों के मूल निवासियों की कला, संस्कृति रहन-सहन, बोलचाल औरों से काफी अलग है, ऐसी स्थिति में इनके संरक्षण के लिए इनर लाइन परमिट व्यवस्था को लागू करना बहुत जरूरी है ताकि बाहरी लोग इधर की संस्कृति को प्रभावित न कर सकें।
- 1950 में, भारत सरकार ने "ब्रिटिश विषयों" को "भारत के नागरिक" के साथ बदल दिया, ताकि उनके हितों की रक्षा के बारे में स्थानीय चिंताओं को दूर किया जा सके।

सोशल एक्टिविस्ट एंजेला रंगाद ने एक दूसरे को बेहतर ढंग से जानने और व्याप्त अफवाहों पर काबू पाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि "हमें बाहरी व्यक्ति से खतरे के विचार को चुनौती देने की जरूरत है।" हमें समझना होगा कि वास्तव में हमें खतरा किससे है। यहाँ लोग आजीविका कमाने के लिए आ रहे हैं, तो वे क्यों स्वदेशी लोगों को धमकी देंगे? बाहरी लोगों के आने और उनके काम करने और कमाने से संबंधित हमारे पास सख्त श्रम कानून होने चाहिए।

मुखीम ने कहा कि "हमारे युवा काम और शिक्षा के लिए भी आगे बढ़ रहे हैं। यदि दिल्ली या बेंगलुरु में उनके साथ इस तरह कि मारपीट या उन्हें वापस जाने के लिए कहा जाये तो फिर उन पर क्या गुजरेगा? आदिवासियों को दी जा रही धमकियों और उनकी असुरक्षाओं को दूर करने के लिए, रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराये जाने चाहिए और यह सब मुमकिन है यदि शासन से जुड़े लोगों के अंदर एक बड़े उद्देश्य के साथ सेवा करने की प्रतिबद्धता हो।"

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. हाल ही में **CAA** को लेकर मेघालय में जातीय हिंसा की घटना देखी गई है। मेघालय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. मेघालय पूर्वोत्तर का एक आदिवासी बहुसंख्यक राज्य है।
2. असम से 1973 में अलग होकर मेघालय एक स्वतंत्र राज्य बना था।
3. CAA छठीं अनुसूची के क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जिसमें मेघालय शामिल है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) 1 और 2

(c) 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

Expected Questions (Prelims Exams)

Q. **Recently incidents of ethnic violence have been witnessed in Meghalaya related to CAA. Consider the following statements related to Meghalaya:**

1. Meghalaya is a tribal majority state in the Northeast.
2. In 1973 Meghalaya became an independent state by separating from Assam.
3. CAA will not be applicable to the areas of the Sixth Schedule which include Meghalaya.

Which of the above statements is/ are correct?

(a) Only 1 (b) 1 and 2

(c) 1 and 3 (d) All of the above

नोट : 05 मार्च को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (d) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. 'मेघालय में मौजूदा हिंसा का कारण राज्य में गैर-आदिवासियों के हितों की रक्षा करने में राज्य की विफलता है।' इस कथन के संदर्भ में मेघालय में हो रही हिंसा के लिए उत्तरदायी कारकों पर चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

'The current spell of violence in Meghalaya is due to it's failure to protect interests of non-tribals in the state.' In the context of this statement give an account of various factors responsible for this violence in Meghalaya. (250 words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।